भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3060

उत्तर देने की तारीख 19 मार्च 2026

उत्तराखंड में मोबाइल नेटवर्क

3060. श्री महेंद्र भट्टः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की उत्तराखंड के पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने गांवों को 4जी/5जी सेवाओं से जोड़ा गया है;

(घ) क्या भारतनेट अथवा अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत दूरस्थ गांवों में ब्रॉडबैंड और हाई स्पीड इंटरनेट सुविधाएँ उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) सरकार ने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के माध्यम से पहाड़ी और सीमावर्ती गांवों सहित सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मोबाइल परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। 28.02.2026 तक, इन परियोजनाओं के माध्यम से 557 टावरों को चालू करके उत्तराखंड के 1,231 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। उत्तराखंड के 16,456 गांवों में से 16,305 गांवों (भारत के महापंजीयक के नवंबर, 2019 के आंकड़ों के अनुसार) में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि 4,729 गांवों में 5जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। 28.02.2026 तक, देश में उत्तराखंड की 1,993 ग्राम पंचायतों सहित देश की 2,14,921 ग्राम पंचायतों को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने लगभग 2.64 लाख ग्राम पंचायतों को रिंग आधारित कनेक्टिविटी और बिना ग्राम पंचायत वाले 3.8 लाख गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संशोधित भारत नेट कार्यक्रम **(एबीपी)** को अनुमोदित किया है।

*****